मालेगांव में सब आरोपी बरी, लेकिन दिलीप की गुमशुदगी के लिए कौन दोषी...?

दुपाड़ा से दिलीप पाटीदार को महाराष्ट्र एटीएस ले गई थी, 17 साल से नहीं पता दिलीप पाटीदार कहां है

शाजापुर, 31 जुलाई. देश के सबसे चर्चित 2008 का मालेगांव विस्फोट आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र एटीएस ने एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें शाजापुर जिले के दुपाड़ा निवासी दिलीप पाटीदार का नाम भी शामिल था. आज मालेगांव विस्फोट मामले का एनआईए के विशेष न्यायालय द्वारा फैसला आया, जिसमें सात आरोपियों को बरी किया गया. इसमें अभी भी दो आरोपी फरार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुपाड़ा के दिलीप पाटीदार को महाराष्ट्र एटीएस विस्फोट के तुरंत बाद इंदौर स्थित निवास से पकड़कर ले गई थी, लेकिन आज 17 साल बाद भी दिलीप का कोई पता नहीं है. मामला उच्च न्यायालय तक भी पहुंचा, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने दिलीप पाटीदार को पकड़ने की बात से इंकार कर दिया. लेकिन दिलीप पाटीदार के परिजनों ने लगातार दिलीप पाटीदार के लिए एटीएस से गुहार लगाई. लेकिन आज दिनांक तक दिलीप पाटीदार का कोई पता नहीं है कि आखिरकार उसे कौन सी एटीएस ले गई.

गौरतलब है कि 10 नवंबर 2008 को दिलीप पाटीदार जो दुपाड़ा निवासी हैं को महाराष्ट्र की एटीएस पुलिस पूछताछ के नाम पर दिलीप को उसके इंदौर स्थित घर से उठाकर ले गए थे. लेकिन इसके बाद से दिलीप घर नहीं पहुंचा. वहीं पुलिस भी इस मामले में उस समय खुलकर कुछ नहीं बोल रही थी. दिलीप के परिजन आज भी चिंतित हैं. इस बात की सूचना परिजनों ने पहले भी हर जगह दी. दिलीप के भाई रामस्वरूप पाटीदार ने दिलीप को छुड़ाने के लिए पूर्व में हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी. साथ ही उसकी हत्या का शक भी जताया था. इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश देते हुए समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था. दिलीप के नहीं मिलने पर कोर्ट को भरोसा दिलाया गया था कि एटीएस के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने के लिए चालान पेश किया जाएगा, लेकिन सीबीआई ने कुछ दिनों पहले क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि एटीएस के अधिकारी मामले में जिम्मेवार तो हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने केस चलाने की अनुमति आज दिनांक तक नहीं दी.

एक साल पहले दिलीप के पिता का हुआ निधन

ये भी संयोग है कि आज मालेगांव विस्फोट के मामले में कोर्ट का फैसला आया और आज ही के दिन एक साल पहले दिलीप पाटीदार के पिता दुपाड़ा निवासी देवीसिंह पाटीदार का निधन हुआ था. आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी, लेकिन आज भी दिलीप पाटीदार का गुमशुदगी रहस्य बनी हुई है. आखिर दिलीप पाटीदार को एटीएस अपने साथ ले गई या नहीं, ये सवाल भी 17 साल बाद वहीं का वहीं खड़ा है.

हाई कोर्ट ने लगाई थी सीबीआई को फटकार

मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह रहे दिलीप पाटीदार के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने वाली सीबीआई को इंदौर की अदालत ने जून 2014 में फटकार लगाई थी. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि आखिरकार मामले की जांच किस आधार पर की गई और क्लोजर रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज और केस डायरी पेश क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने 10 जुलाई 2014 तक सीबीआई को पूरे दस्तावेज पेश करने को कहा था. सीबीआई कोर्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सीबीआई के वकील ने उन दिनों क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. उसमें कहा गया था कि पाटीदार को ले जाने वाले एटीएस के अधिकारी जिम्मेवार तो हैं, लेकिन उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार केस चलाने की अनुमति नहीं दे रही. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए केस से जुड़े पूरे दस्तावेज पेश करने को कहा था.

महाराष्ट्र एटीएस के कमिश्नर और इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था

दिलीप पाटीदार के मामले में सीबीआई ने 21 मई 2014 को क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने कुछ बिंदुओं के साथ वापस लौटा दी थी. इसके बाद सीबीआई ने नए बिंदुओं पर जांच करने के बजाय 23 सितंबर 2015 को दोबारा क्लोजर रिपोर्ट सौंपी. लेकिन 26 मई 2016 को स्पेशल सीबीआई जज ने दिलीप पाटीदार के मामले में महाराष्ट्र एटीएस के असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 120 बी, 342, 344, 348, 193, 218, 365 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जून 2016 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक ना ये अधिकारी कोर्ट के सामने पेश हुए और ना ही दिलीप पाटीदार का कोई पता चला.

दिलीप को इसलिए ले गई थी एटीएस...

जानकारी के अनुसार दिलीप कनाड़िया रोड स्थित शांति विहार कॉलोनी में पत्नी-पुत्र के साथ किराए से रहकर इलेक्ट्रिक का काम करता था. वह शाजापुर जिले के दुपाड़ा गांव का था. मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई एटीएस ने 16 अक्टूबर को शांति विहार कॉलोनी निवासी शिवनारायण कलसांगरा, श्याम साहू, दिलीप नाहर व देवास के धर्मेंद्र बैरागी को हिरासत में लिया था. इसके करीब एक हफ्ते बाद सूरत में पकड़ी गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ शिवनारायण व श्याम को भी ब्लास्ट का आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया. 31 अक्टूबर की देर रात एटीएस अफसर शिवनारायण को लेकर उसके घर पहुंचे. वहां तलाशी ली और उसकी लाइसेंसी बंदूक ले गए. यह दृश्य किराएदार दिलीप पाटीदार ने देखा था. बाद में शिवनारायण के पिता गोपालसिंह ने खजराना थाने में एटीएस अफसरों के खिलाफ गहने चोरी की रिपोर्ट के लिए आवेदन दिया था. परिजनों के मुताबिक इसमें वे फंस सकते थे, इसलिए चश्मदीद गवाह दिलीप को 10 नवंबर 2008 की रात में ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए ले गए. बता दें 11 जुलाई, 2011 की सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिलीप पाटीदार को उसके घर से 10-11 नवम्बर 2008 की रात को एटीएस मुंबई की टीम ने हिरासत में लिया था. बताया जाता है कि उसे 20 नवंबर तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया. जबकि उसके कहीं ले जाने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं थी. ना कोई नोटिस या सम्मन जारी किया गया नहीं था.

एक नजर में

क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आज से शुरू होगी पंजीयन प्रक्रिया

शाजापुर, 31 जुलाई. जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिससे वे अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं. इसके लिए खिलाड़ियों को अपने क्लब से आवेदन करवाना होगा. वहीं जो खिलाड़ी किसी क्लब से संबद्ध नहीं है वे सचिव से संपर्क कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं. जिला क्रिकेट एसोसिएशन सचिव मनोज आर्य ने बताया कि संभागीय संगठन के निर्देश अनुसार शाजापुर जिले की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि अपने पंजीयन के लिए खिलाड़ी जिले में संचालित अपने क्लब के माध्यम से पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, समग्र आईडी के साथ पिछले तीन सालों की अंकसूची भी लाना होगी. उन्होंने बताया कि यदि कोई खिलाड़ी किसी क्लब से संबद्ध नहीं है और उसमें प्रतिभा है उसे भी मौका दिया जाएगा. इसके लिए वह भी सचिव से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकता है. यह जानकारी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सहसचिव आनंद भावसार ने दी.

जल संसाधन विभाग ने समयपाल व चौकीदार को दी विदाई

सुसनेर, 31 जुलाई. गुरुवार को जल संसाधन विभाग के समयपाल कैलाश राठौर व नाहरखेड़ा बांध के चौकीदार रमेशचंद्र बिकुंदिया कि सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह का आयोजन डाक बंगला रोड़ पर स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में किया गया. यहां पर अधिकारियों ने दोनों का सांफा बांधकर, फूलमाला पहनाकर व शॉल श्रीफल भेंटकर स्वागत व सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की. उसके पश्चात सेवानिवृत्ति की यादे सहेजने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रजाति के 10 पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस अवसर पर एसडीओ गोविंद पाटीदार, सब इंजीनियर आनंद वर्मा, स्वरूप मालवीय, मनोज जैन, मोहन भिलाला, चौकीदार मेहरबान सिंह गणेशपूरा, शांतिलाल पीलियाखाल, लालसिंह किटखेड़ी, दुर्गाशंकर श्रीवास्तव बोरखेड़ी, दिनेश शर्मा, मप्र जन अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक सत्यनारायण सोनी आदि मौजूद रहे.

विधायक के जन्मदिन पर अस्पताल में बांटे फल, बिस्किट

सुसनेर, 31 जुलाई. गुरूवार को क्षेत्रिय विधायक भैरोसिंह परिहार बापू के जन्मदिन के अवसर पर नगर के पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में उनके समर्थको के द्वारा मरीजों को फल बिस्कीट वितरित कर सभी मरीजों के जल्द ही स्वस्थ्य होने की कामना की. इस अवसर पर बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे.

मोरूखेडी के लिए आज निकलेगी कावड यात्रा

सुसनेर, 31 जुलाई. नगर के मेला ग्राउंड स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से मोरूखेडी स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तक कावड व कलश यात्रा निकाली जाएगी. इसको लेकर समिति के द्वारा कई दिनों से तैयारीयां की जा रही है. शुक्रवार की सुबह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में विधिवित रूप से पूजा अर्चना की जाएगी. उसके पश्चात यात्रा की शुरूआत होगी जो नगर के विभिन्न् मार्गो से होते हुएं मोरूखेडी स्थित अतिप्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी. यहां पर क्षेत्रवासियो की सुख समृद्धि की कामना को लेकर महोदव का जलाभिषेक किया जाएगा.

नकली कीट नाशक से 700 बीघा जमीन में 115 किसानों की फसल नष्ट

सुसनेर, 31 जुलाई. क्षेत्र में नकली कीटनाशक खुलेमाम बिक रही हैं इससे किसानों की फसल भी नष्ट हो रही हैं नकली खरपतवार नाशक दवाई के उपयोग से करीब 115 किसानों की 700 बीघा सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई. इस नुकसान की भरपाई और संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को किसानों ने एसडीएम सर्वेश यादव, कृषि विभाग व स्थानीय पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है. ज्ञापन में बताया गया कि सुसनेर में पिड़ावा रोड इमली चौराहे पर एककीटनाशक की दुकान है. जानकारी के अनुसार दुकान संचालक ने खरपतरवार नाशक दवाई मंगवाकर करीब 115 किसानों को बेची थी. खेतों में खरपतवार तो नष्ट नहीं हुई, बल्कि सोयाबीन की फसलें चौपट हो गईं. इस बारे में संबंधित कंपनी के अधिकारियों को अवगत कराया गया. लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार निरीक्षण करने नहीं आया. इसलिए किसानों को फसल का सर्वे करवाकर कंपनी से तत्काल मुआवजा दिलवाया जाए तथा कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. ज्ञापन सौंपते समय गोकुल सिंह सादलपुर, लालसिंह, हेमराज सिंह धन्याखेडी, विक्रम सिंह ननौरा, बालूसिंह, उदा लाल बड़ा दरिया, बालू सिंह, मनोहर सिंह, टके सिंह सारसी आदि उपस्थित रहे.

पिपलिया खेड़ा बालाजी मंदिर पर धूमधाम से मनाई तुलसी दास जयंती

सोयतकलां, 31 जुलाई. सोयतकलां से 12 किलोमीटर दूर प्रसिद्धधार्मिक स्थान पिपलिया खेड़ा बालाजी मंदिर पर श्री बालाजी मित्र मंडल के तत्वाधान में तुलसी दास जी कि 528 जयंती मनाने के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में मानस प्रेमियों ने भाग लिया. हारमोनियम ढोलक संगीत के साथ 108 सुंदरकांड का पाठ मंदिर परिसर में किया गया तथा सामूहिक सहभोज का आयोजन हुआ.

गो-अभयारण्य में गोवंश को लेकर विवाद पहुंचा थाने

सालरिया, फरसपुरा व ग्राम खोयरिया के ग्रामीणों ने थाने पर दिया आवेदन

झूठी शिकायत करने का लगाया आरोप

सुसनेर, 31 जुलाई. विश्व के प्रथम कामधेनु गो अभयारण्य सालरिया में फरसपुरा, सालरिया व खोयरिया आदि ग्रामों के गोवंशों को नहीं रखे जाने को लेकर अभयारण्य प्रबंधन व ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. कुछ दिनों पूर्व ग्रामीण गोवंश को अभयारण्य में छोड़कर आए थे उसके बाद प्रबंधन की शिकायत पर सुसनेर पुलिस ने 5 से 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया.

इसके विरोध स्वरूप गुरुवार की दोपहर 12 बजे सालरिया, फरसपुरा व खोयरिया के ग्रामीण बड़ी संख्या में सुसनेर पुलिस थाने पहुंचे और थाना प्रभारी केसर राजपूत को मामले से अवगत कराते हुए अभयारण्य प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध की गई झूठी शिकायत को झूठी बताते हुए निरस्त करने की मांग की. दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि उपरोक्त ग्रामों एवं ग्राम पंचायत में शासन के द्वारा किसी भी प्रकार से गो शाला का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर शासन के द्वारा गो अभयारण्य बनाया गया है, इस कारण से संबंधित ग्रामों में आसपास के गांव के लोगों के द्वारा आकर गायों को छोड़ दिया जाता है. जिसके कारण से हम ग्राम के किसानों की फसलें उक्त गायों के द्वारा बर्बाद कर दी जाती है इस कारण से हमारे द्वारा लगभग 100 मवेशियो को सालरिया गो अभ्यारण में छोडने के लिए 29 जुलाई को गए तब वहां पर पदस्थ गोशाला प्रबंधक शिवराज शर्मा के द्वारा हम ग्रामीणों के साथ में गाली गलौच की गई एवं अभद्र व्यवहार किया गया है. हमारे द्वारा जो गाये ले जायी गई थी उनको गोअभयारण्य में रखने से साफ इंकार कर दिया और गायों को भगा दिया. जिसके संबंध में थाना प्रभारी के मौके पर आने पर दोनों पक्षों को समझा दिया गया था किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता मौके पर नहीं की गई थी. उसके बावजूद भी गोशाला प्रबंधक के द्वारा पुलिस थाना सुसनेर मे आकर हमारी झूठी शिकायत भी नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज करवा दी गई है. जिससे ग्रामीणों मे काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है एवं एक तरफ तो ग्रामीणों की फसलें गायों द्वारा बर्बाद की जा रही है. दूसरी ओर ग्रामीणों द्वारा गायों को सुरक्षित स्थान पर रखे जाने का प्रयास किया जाता है तो उनके खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है. इस कारण से विवश होकर यह आवेदन देना आवश्यक हुआ है. अत: ग्रामीणों के खिलाफ जो झूठी शिकायत की गई है उसके भी सत्यता पूर्वक जांच के जाकर उचित कार्रवाई की जाए. इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीनों ग्रामों के ग्रामीण उपस्थित रहे.

भवन का अभाव, प्रार्थना के बाद बच्चे भेज दिए जाते हैं घर

मोहन बड़ोदिया, 31 जुलाई. विकासखंड के ग्राम करजू में कक्षा 1 से 10 तक कुल 200 बच्चे अध्यनरत हैं, किंतु बिल्डिंग का अभाव, स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि लगातार विद्यालय भवन के निर्माण को लेकर शिक्षा मंत्री के पास तक चले गए किंतु भवन का निर्माण अभी तक नहीं करवा पाए, हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया विकासखंड के ग्राम करजू के शासकीय विद्यालय भवन की. यहां प्राथमिक और माध्यमिक भवन की बिल्डिंग 50 वर्ष पुरानी है जो जर्जर हालत में है छत से मलबा गिर रहा है.भवन के अंदर तेज बारिश होने पर पानी आ जाता है.

ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो दूर बैठने की जगह की समस्या आ जाती है. ग्राम पंचायत सरपंच राधेश्याम आर्य ने बताया कि विद्यालय भवन के लिए कुल साढ़े सात बीघा जमीन सुरक्षित कर रखी है. किंतु विभाग से विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल रही है. ऐसे में कहा जा सकता है कि हाई स्कूल की बिल्डिंग तो है ही नहीं क्योंकि जो अतिरिक्त कक्ष में हाई स्कूल के छात्र बैठे हैं वह ग्राम पंचायत के अतिरिक्त भवन हैं. जिनमें हाई स्कूल संचालित हो रहा है. शासन लगातार आरटीई के मापदंड की बात करता है किंतु उन्हीं के विद्यालयों में इसका पालन नहीं हो रहा है. प्रभारी प्राचार्य मोड़सिंह भिलाला ने बताया कि 2002 से हाई स्कूल संचालित हो रहा है. किंतु शासन प्रशासन को भी लगातार विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की जा रही है. वहीं अतिरिक्त कक्षों में हाई स्कूल की कक्षाएं संचलित हो रही उसमें भी दो कमरों को छोड़कर सभी में पानी टपक रहा है और छत से सीमेंट कांक्रीट गिर रहा है. जिससे सिर्फ प्रार्थना करवाकर छात्रों को घर भेज दिया जाता है. इस मामले में ग्राम पंचायत करजू के उपसरपंच यशवंत आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराने पर सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया ने भी 26 अक्टूबर 2021 को कार्यपालन यंत्री शाजापुर को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया था कि एकीकृत शाला भवन शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है इसलिए इसे राइट ऑफ करने की अनुमति दी जाए. ऐसे में बच्चे इसी भवन में बैठे हैं, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा.

वृद्धजनों को सहायक उपकरण के लिए परीक्षण शिविर संपन्न

शाजापुर, 31 जुलाई. कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशानुसार जिले में एलिम्को उज्जैन द्वारा आज एक दिवसीय चिन्हाकन शिविर सम्पन्न हुआ.जिसमें जिले के 126 वृद्धजनों का परीक्षण किया गया. शिविर में 91 वृद्धजनों का चिन्हांकन/ परीक्षण किया गया. जिसमें जिले के वृद्धजनों को कॉन की मशीन, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, कमर, घूटने, गले का बेल्ट आदि सहायक उपकरण के लिए 91 वृद्धजनों का चिन्हांकन परीक्षण किया गया.

एक नजर में — जिला प्रशासन के कई नवाचारों की मुख्यमंत्री ने की तारीफ, शासन स्तर पर भी हुई सराहना

शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, किसान के मामले में कर्मशाला को बनाया प्रयोगशाला

शाजापुर, 31 जुलाई. शासन और प्रशासन के कामों को अमलीजामा पहनाने के लिए और मैदानी इलाकों तक सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण संभव हो, इसके लिए जिले के मुखिया के तौर पर यह दायित्व कलेक्टर का होता है. क्योंकि सरकार तो योजना बना देती है, लेकिन उसे जनता तक पहुंचाने का काम प्रशासन का होता है. यदि प्रशासन में अधिकारी जनहित के मुद्दे पर स्वप्रेरणा और स्वरुचि रखे, तो शासन की योजनाएं जन-जन तक पहुंच जाती है. सीधी भर्ती की आईएएस अधिकारी और शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना ने अपने 520 दिन के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और किसानों के हित के मामले में लगातार कई काम किए. लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया और आम जनता की शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुना. कुछ नवाचार ऐसे रहे, जिनको पूरे प्रदेश स्तर पर शाजापुर कलेक्टर की पहल को लागू करने की बात भी कही गई. कुछ मामलों में तो मुख्यमंत्री ने शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना के अच्छे काम की प्रदेश के अधिकारियों के सामने तारीफ भी की.

गौरतलब है कि सीएम हेल्पलाईन में अक्टूबर 2024 से लगातार ग्रेड 1 के साथ शाजापुर जिला प्रदेश में टॉप 5 में रहा. मई और जून 2025 के महीने में लगातार प्रदेश स्तर की जारी रैंकिंग में शाजापुर प्रथम आया. इसी प्रकार जिला स्तर पर नवाचार करते हुए पंचायत अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी एक ही पत्रक पर उपलब्ध हो, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2024 से शुरू की थी. प्रतिमाह पंचायतों को उपलब्ध कराया गया था, जिसे पंचायत भवन में रखा जाए, जिसे पंचायत अंतर्गत संचालित योजनाओं में पारदर्शिता आई, निकाय एवं शासकीय अमले की जवाबदेही बढ़ी. परिणाम स्वरूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा की हितग्राही मूलक योजनाओं के लक्ष्य अच्छे मिले. जल संरक्षण की बात करें, तो शाजापुर जिला भूजल दोहन की श्रेणी में अतिदोहित होने से भूजल स्तर में सुधार एवं वृद्धि हेतु वर्ष 2024 में मनरेगा योजना से 120 बोल्डर नाला बंधान एवं गेवियन संरचना का निर्माण कराया गया.

जिससे 1.15 लाख घन मीटर भूजल रिचार्ज हो रहा है. साथ ही जागरुकता के माध्यम से 438 बोरी बंधान, 64 स्टॉप डेम पर गेट लगाकर 743000 घन मीटर वर्षा जल संरक्षित हुआ है, जिससे जिले में 938 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है. आजीविका मिशन के अंतर्गत शाजापुर जिले में 17 क्लस्टर संगठित गठित किए. जिसमें 11 क्लस्टर संगठनों को खाली पड़े सरकारी भवन उपलब्ध कराए गए. संगम सीएलएफ ने शाजापुर ब्लॉक में रोजगार आधारित रेडिमेड सिलाई का काम शुरू किया. शुजालपुर ब्लॉक में पेपर प्लेट, पेपर कप, अन्य डिस्पोजल निर्माण इकाई शुरू की. मो. बड़ोदिया में मलासा पैकिंग इकाई शुरू की, तो कालापीपल ब्लॉक में पापड़ निर्माण इकाई शुरू कर आजीविका मिशन अंतर्गत रोजगार के अवसर प्रदान किए. कहा जाता है कि तन स्वस्थ, तो मन स्वस्थ. जिले में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकारी अस्पताल अंतर्गत हाइड्रोलिक लेबर बेड, सीटर बेटिंग चेयर, मशीनीकृत लॉन्ड्री और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए वातावरण. पूर्ण टीकाकरण में 98.41 प्रतिशत सफलता. एएनसी पंजीकरण में 65.66 प्रतिशत, टीबी नियंत्रण में 2023 से बढ़कर सकारात्मक दर 1.4 तक. तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा में शाजापुर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर पिछले साल की तुलना में तीसरे पायदान पर रहा. जो विगत वर्ष 16वें स्थान पर था. बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन स्तर पर केंद्रीकृत और लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को जिलास्तरीय समीक्षा बैठक के लिए बुलाया गया और संकूलों में शिक्षकों की तैनाती और उनकी लामबंदी से स्कूलों में निर्बाध और नियमित शिक्षण सुनिश्चित किया गया. राष्ट्रीय परख योजना में 2024 में एनएएस के मामले में शाजापुर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में कक्षा 3 के लिए शीर्ष 20 जिलों में स्थान प्राप्त किया.

किसानों को खाद के लिए टोकन प्रणाली की सराहना

बोवनी के समय किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खाद की उपलब्धता रहती है. कलेक्टर ऋजु बाफना ने किसानों को शीघ्र खाद मिले, इस उद्देश्य से जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर उसके माध्यम से खाद की टोकन प्रणाली की शुरुआत की, जिसके माध्यम से रबी एवं खरीफ की फसलों के दौरान जिले के किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, जिस पर किसानों द्वारा मांग दर्ज कराने पर उनके एसएमएस के माध्यम से खाद की सूचना एवं तारीख दी जाती थी. और किसान खाद वितरण केंद्र पर पहुंचकर आसानी से खाद प्राप्त कर सकता था. लगभग 6500 किसानों द्वारा टोकन प्रणाली के माध्यम से खाद प्राप्त किया, इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टोकन प्रणाली की तारीफ करते हुए खाद उपलब्धता के मामले में पूरे प्रदेश में यह प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे. ये नवाचार शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना ने शुरू किया था. इसी प्रकार फार्मर रजिस्ट्री के क्षेत्र में शत-प्रतिशत काम किया गया. सरकारी मंदिरों के संधारण के लिए ई-डायरेक्ट्री और पुजारियों की पूरी जानकारी मंदिर की सम्पत्ति, मंदिर में स्थापित मूर्तियों की जानकारी, आमजन को मिले, इसके लिए वेबसाईट तैयार की गई, जिससे शासन संधारित मंदिरों की जानकारी आमजनों के लिए आसान हो.